आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 21.02.2026, समय 1830

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय संस्कृति की सराहना की और समुदाय के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा– राष्ट्र की सुरक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक जागरूक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे 'मन की बात' कार्यक्रम में देश–विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे।
- और, अमरीका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ अस्थायी तौर पर कम करके 10 प्रतिशत करने की घोषणा की।

जनजातीय समागम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनजाति समाज केवल एक वर्ग विशेष नहीं, बल्कि देवभूमि की आत्मा है। चमोली में आयोजित जनजातीय समागम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जनजातीय संस्कृति की सराहना की और समुदाय के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सदियों से परंपराओं और लोक संरक्षण की भावना के साथ जनजाति समाज ने हमारी सभ्यता को पहचान देने का कार्य किया है।

श्री धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 128 गांव चिन्हित किए गए हैं, जहां रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ–साथ बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस बीच, मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में आगामी कुंभ–2027 की तैयारियों की समीक्षा भी की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार कुंभ के साथ–साथ इस वर्ष की चारधाम यात्रा की तैयारियों में भी जुटी है। यात्रा को पहले से अधिक सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जा रहे हैं।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक जागरूक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। वे आज पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर

स्थित मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिक खतरों की पहचान कर उन्हें संबंधित तंत्र तक पहुंचाते हैं, राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करते हैं तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जनरल चौहान ने कहा कि मेडिकल छात्रों को समाज का स्वास्थ्य रक्षक बताते हुए कहा कि आपदा, महामारी एवं आपात परिस्थितियों में उनकी भूमिका सीधे राष्ट्रसेवा से जुड़ी होती है।

सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कार्रवाई प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि आतंकी ढांचों को लक्षित कर नई सामान्य स्थिति स्थापित करने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम था। उन्होंने कहा कि जागरूक और सशक्त नागरिक ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं तथा चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के 'मन की बात' कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 131वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ऑनएयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कई तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए गए। श्री वैष्णव ने आज सुबह समिट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि युवाओं में एआई समिट को लेकर बहुत उत्साह है। उन्होंने समिट स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में कांग्रेस कार्य़कर्ताओं के कल हंगामा करने पर कहा कि लोगों ने इसे बेहद शर्मनाक बताया।

आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के के पंत ने कहा की भारत में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की बेहतर निगरानी, कृषि, मौसम, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में एआई मददगार हो सकता है।

माओवाद

गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल–सी.आर.पी.एफ. के 87वें स्थापना दिवस परेड समारोह में कहा कि देश ने अगले महीने की 31 तारीख तक माओवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है।

टैरिफ

व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा नए वैश्विक टैरिफ की घोषणा के बाद भारत को अस्थायी रूप से 10 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।

धारा 122 के अन्तर्गत घोषित 10 प्रतिशत का यह नया टैरिफ कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं है, बल्कि यह पहले के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम पर आधारित शुल्कों का स्थान लेगा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

इसी बीच,विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अमरीका हाल ही में अपनाए गए संयुक्त वक्तव्य के अनुसार पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं।